TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 214
दि. 05.12.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सामने आए सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी कार्यकताओं को दे दिया ये मंत्र

यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पात्र वोटरों का नाम किसी भी स्थिति में न छूट जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास हो रहा है। सीएम योगी ने इस मामले में निर्देश दिया है।

लखनऊः (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम राजधानी लखनऊ स्थित एनेक्सी भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में भाजपा पदाधिकारियों, पार्षदों, पूर्व पार्षदों और वार्ड चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (रक्क) अभियान में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसे में भाजपा कार्यकताओं और पार्षदों को पूरी मजबूती के साथ घर-घर पहुंचकर मतदाताओं की सहायता करनी होगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए। घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएं और 5झ10 दिसंबर तक हर बूथ पर विशेष कैंप लगाएं। सीएम ने कार्यकताओं को बड़ा टास्क दिया है। दरअसल, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) में ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का विवरण भरवा रहे हैं। इस प्रपत्र में मतदाता का नाम, आयु, पता, पारिवारिक जानकारी आदि शामिल होती है।

सीएम योगी ने क्या कहा?

सीएम योगी ने कहा कि बीएलओ के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने में सहयोग करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र मतदाताओं का प्रपत्र जमा हो जाए। मृतक या फर्जी मतदाताओं के नाम सूची से हटाने में भी कार्यकर्ता मदद

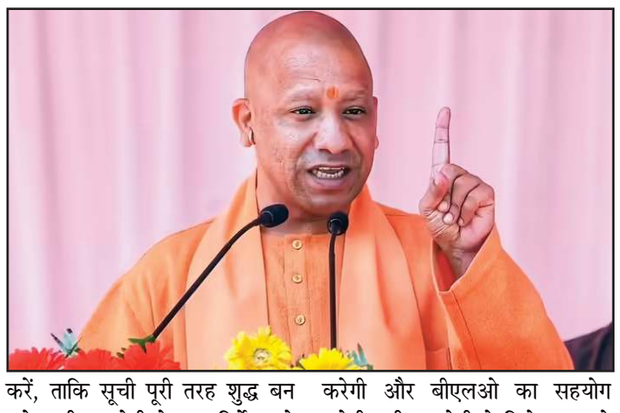

करें, ताकि सूची पूरी तरह शुद्ध बन सके। सीएम योगी के इस निर्देश को लेकर अलग चर्चा तेज हो गई है।

हर बूथ पर 10 सदस्यीय टीम

मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष, बीएलए, बूथ समिति सदस्य, वरिष्ठ कार्यकर्ता की 10 सदस्यीय टीम गठित की जाए, जो एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी करेगी और बीएलओ का सहयोग करेगी। सीएम योगी ने विशेष रूप से कहा कि महिला मतदाताओं को फॉर्म भरने में परेशानी न हो, इसके लिए भाजपा की महिला कार्यकताओं की एक अलग टोली बनाई जाए।

सीएम योगी ने कहा कि यह टोली घर-घर जाकर महिला मतदाताओं का फॉर्म भरवाएगी। कैंपों में सहायता करेगी। छूटे हुए फॉर्म भरवाने में मदद करेगी। फॉर्म भरने के बाद डिजिटल एंट्री पर जोर दिया है।

योगी आदित्यनाथ ने कार्यकताओं से कहा कि केवल फॉर्म भरवाना पर्याप्त नहीं है। उसे डिजिटल कराना और ई-रोल में सही ढंग से दर्ज कराना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यकताओं से अपील की कि वे लोगों की डिजिटल एंट्री करवाने में भी सहायता करें। खासकर उन लोगों की, जिन्हें डिजिटल प्रक्रिया समझने में कठिनाई होती है।

सीएम ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। ऐसे में फर्जी मतदाताओं के नाम हटवाए जाएं। मृतक मतदाताओं के नाम सूची से हटे हों, इसकी पुष्टि की जाए। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि कार्यकताओं की भी है।

सीएम योगी ने सभी बूथों पर 5झ10 दिसंबर तक विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। इन कैंपों में गणना प्रपत्र जमा किए जाएंगे। लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने-संशोधन में सहायता दी जाएगी। डिजिटल एंट्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

'भारत भाग्यशाली है, मोदी देश के लिए जीते और सांस लेते हैं', पीएम मोदी के मुरीद हुए पुतिन, जमकर की तारीफ

(एजेंसी)।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चार साल से अधिक समय बाद भारत की अपनी पहली दो दिवसीय यात्रा गुरुवार शाम को शुरू की। 4 दिसंबर को शाम 7 बजे दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पुतिन के उतरने पर, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए व्यक्तिगत रूप से रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए पुतिन से पहले हाथ मिलाया और इसके बाद गले लगाकर उनका अभिनंदन किया।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा,"भारत भाग्यशाली है कि उसे पीएम मोदी जैसा नेता मिला।

पुतिन ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा, "प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए जीते और सांस लेते हैं," उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्कों पर पीएम मोदी के रुख की भी सराहना की! पुतिन ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी "दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं।" "पीएम मोदी किसी दबाव में झुकते नहीं, डट कर खड़े रहते हैं"

पुतिन ने कहा, "भारत एक महान शक्ति है, कोई अंग्रेजी या ब्रिटिश उपनिवेश नहीं, और सभी को इसे

ध्यान में रखना होगा।" उन्होंने भारत-रूस के ऐतिहासिक रक्षा और व्यापार संबंधों पर भी जोर दिया। पुतिन ने कहा कि भारतीय वास्तव में अपने नेता पर गर्व कर सकते हैं क्योंकि "प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आसानी से दबाव के आगे झुकते हों।" पुतिन ने आगे कहा , " पीएम मोदी का रुख अटल और सीधा है, बिना किसी टकराव के।हमारा लक्ष्य संघर्ष को भड़काना नहीं है; बल्कि, हमारा लक्ष्य अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है। भारत भी ऐसा ही करता है।" "पीएम मोदी से मिलना दिलचस्प होता है" पुतिन ने मोदी से बातचीत को "बड़ा सुखद" अनुभव बताया और उन्हें "ईमानदारी वाला व्यक्ति" कहा। वह भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग, रक्षा, मानवीय जुड़ाव व उच्च-प्रौद्योगिकी जैसे व्यापक क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। उनसे मिलना बहुत दिलचस्प होता है।"

प्रधानमंत्री मोदी की पिछली मास्को यात्रा के दौरान, पुतिन ने याद किया कि उनके बीच "पूरी तरह से दोस्तों जैसी" दिलचस्प बातचीत हुई थी। पुतिन ने बताया, "वह मेरे निवास पर आए, हमने पूरी शाम चाय पीते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की।"

गौरतलब है कि राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर गुरुवार को दो दिवसीय नई दिल्ली दौरे पर पहुँचे। यह यात्रा वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद आठ दशकों पुरानी द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसमें रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रमुख रहेगा।

लगभग तीन महीने पहले, शंघाई सहयोग संगठन (रउड) शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के तियानजिन में मोदी और पुतिन मिले थे। तब पुतिन ने मोदी को अपनी गाड़ी में सैर कराकर एक प्रतीकात्मक हावभाव दिया, जिसने वैश्विक ध्यान खींचा। यह भू-राजनीतिक तनावों व मॉस्को से भारत के संबंधों को लेकर अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच आया था।

संक्षिप्त समाचार

भारत में RT World लॉन्च करेंगे पुतिन, बेरोजगारों के लिए बंपर Jobs! कौन कर सकता है अप्लाई?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। यह उनकी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली भारत यात्रा है, जिस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इसी यात्रा के दौरान रूस का सरकारी टीवी नेटवर्क आरटी (RT) शुक्रवार को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल से अपना भारतीय प्रभाग लॉन्च करेगा। इस दौरान पुतिन का एक छोटा इंटरव्यू भी संभव माना जा रहा है। दिल्ली में लॉन्च होगा RT India, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बने हाई-टेक स्टूडियो और सौ से ज्यादा कर्मचारियों के साथ RT इंडिया, रूस टुडे नेटवर्क का दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी उद्यम बनने जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की किस बात ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कर दिया सरप्राइज?

(एजेंसी)।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा यह दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से है। दिसंबर में होने वाली इस वार्षिक बैठक की मेजबानी भारत और रूस बारी-बारी से करते हैं।

4 दिसंबर को जब रूसी राष्ट्रपति भारत की धरती पर कदम रखा तो वो सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर अचंभित रह गए क्योंकि उनके लिए पीएम मोदी द्वारा एयर पोर्ट पर स्वागत करना एक सरप्राइज था।

काले सूट-बूट पहने पुतिन जैसे ही अपने विशेष विमान से राष्ट्रपति पुतिन पालम हवाई अड्डे उतरे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उनका स्वागत किया।

दरअसल, पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पुतिन को रिसीव करने पहुंचे थे। गर्मजोशी सेउनसे हाथ मिलाया और फिर उन्हें गले लगाया। यह अप्रत्याशित और स्नेहपूर्ण स्वागत रहा।

रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन भी हुआ सरप्राइज

आजतक की रिपोर्ट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि पीएम मोदी के इस अप्रत्याशित स्वागत की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए।

इसके तुरंत बाद, दोनों नेता एक ही टोयोटा एसयूवी में सवार होकर प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए, जहां शिखरवार्ता होनी है।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह दो दिवसीय भारत दौरा खास है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई व्यापार तथा रक्षा सौदे किए जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को पहले कहा था कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका को रूसी ईंधन खरीदने का अधिकार है, तो भारत को "वही विशेषाधिकार" क्यों नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने भारत पर ट्रंप के शुल्कों पर बोलते हुए स्पष्ट किया, "भारत द्वारा रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद के संबंध में, मैं यह पुनः उल्लेख करना चाहूंगा, कि अमेरिका खुद अभी भी अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए हमसे परमाणु ईंधन खरीदता है।"

भारत ने नई दिल्ली में 20वीं यूनेस्को अंतर-सरकारी समिति की मेजबानी की

भारत 8 से 13 दिसंबर 2025 तक लाल किला, नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु अंतर-सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। इसके उद्देश्य

और लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

यूनेस्को आईसीएच सूची में शामिल होने के लिए सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत नामांकनों की जांच करना, मौजूदा तत्वों की स्थिति की समीक्षा करना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ के धोरडो से रणोत्सव 2025-26 का शुभारंभ कराया

धोरडो में रणोत्सव में 'एकत्व झ एक देश, एस गीत, एक भावना' की संस्कृति को उजागर करने वाली कृतियों का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ

मुख्यमंत्री ने कच्छ के पर्यटन को गति देने के लिए लखपत किलो, तेरा हेरिटेज विलेज तथा धोरडो के 179 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण तथा शिलान्यास किया

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुआ रणोत्सव आर्थिक-सामाजिक विकास का श्रेष्ठ उदाहरण तथा ग्लोबल इवेंट बना है
- समाज, संस्कृति एवं समृद्धि के संगम से रचा गया 'धोरडो मॉडल' विश्वभर के विशेषज्ञों के लिए एक केस स्टडी
- रणोत्सव में परंपरागत कच्छी भूंगा तथा आधुनिक टैंट सिटी से प्रधानमंत्री का 'विकास भी, विरासत भी' का दृष्टिकोण साकार हुआ
- रणोत्सव में पर्यटकों की सुविधा के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की राज्य सरकार की मंशा

गांधीनगर,04 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को सफेद रेगिस्तान धोरडो से कच्छ रणोत्सव 2025 का शुभारंभ कराते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कच्छ के रण (रेगिस्तान) को पर्यटन का तोरण (वंदनवार) और विश्व के लिए फेवरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का सपना साकार हुआ है।

इस संदर्भ में श्री पटेल ने जोड़ा कि रणोत्सव अब ग्लोबल इवेंट बन गया है और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से समाज, संस्कृति एवं समृद्धि के संगम से रचा गया धोरडो मॉडल विश्वभर के विशेषज्ञों के लिए केस स्टडी बना है।

मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम् के 150 वर्ष होने के अवसर को जोड़ने वाले 'एकत्व झ एक देश, एक गीत, एक भावना' थीम आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों, कच्छी कला तथा गुजरात की संस्कृति को उजागर करने वाली कृतियों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ रणोत्सव का उद्घाटन किया।

उन्होंने कच्छ के पर्यटन को गति देने के लिए लखपत किला, तेरा हेरिटेज विला और धोरडो के 179 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का ई-लोकार्पण तथा शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा उपस्थित थे।

ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कोहिमा युद्ध समाधि स्थल का दौरा किया और श्रद्धांजलि अर्पित की

पूर्वोत्तर में ऐतिहासिक और उभरते सांस्कृतिक स्थलों का सम्मान

सांस्कृतिक पर्यटन और समुदाय-नेतृत्व वाली गतिविधियों को अधिकतम प्रोत्साहन

(एजेंसी)।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज कोहिमा युद्ध समाधि स्थल का दौरा किया, जहां स्थानीय अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के निर्णायक घटनाक्रमों में से एक कोहिमा के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि यह युद्ध समाधि स्थल साहस, बलिदान और साझा इतिहास का जीवंत प्रतीक है। यह न केवल एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल है, बल्कि ऐसा स्थान भी है जो देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को लगातार आकर्षित करता है।

स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का संबोधन

(एजेंसी)।

अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने आज स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में 'भारत के लोकतंत्र के भीतर' विषय पर एक गोलमेज चर्चा आयोजित की। स्वीडन की पूर्व विदेश मंत्री सुश्री एन लिंडे इस गोलमेज चर्चा में अन्य वक्ता थीं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोल एसिस्टेंस (इंटरनेशनल आईडीईए) के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण किया था। वे आज बाद में अपनी स्वीडन की आधिकारिक यात्रा संपन्न करेंगे।

भारत की अध्यक्षता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो दुनिया के सबसे विश्वसनीय और नवीन चुनाव प्रबंधन निकायों में से एक के रूप में भारत के चुनाव आयोग वैश्विक मान्यता को दशार्ता है। अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने संगठन के शासन, लोकतांत्रिक विमर्श और संस्थागत पहलों में निरंतर योगदान दिया है।

स्टॉकहोम पहुंचने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने स्वागत किया। उन्होंने आईआईडीईए के महासचिव डॉ. केविन कैसास-जमोरा के साथ भी चर्चा की।

स्टॉकहोम में अपने स्वीकृति भाषण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पैमाने पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 900 मिलियन से अधिक मतदाता हैं।

2024 के आम चुनावों पर विचार करते हुए उन्होंने बताया कि भारत ने एक अद्भुत लोकतांत्रिक झांकी देखी, जिसमें 6 राष्ट्रीय और 67 राज्य स्तरीय दलों सहित 743 राजनीतिक दलों के 20,000 से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया। इस प्रक्रिया में 10 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों और 50 लाख से अधिक मतदान कर्मचारियों सहित 2 करोड़ से अधिक चुनाव कर्मी शामिल थे।

उन्होंने कहा कि भारत ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद से संसद के लिए 18 आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के लिए 400 से अधिक आम चुनाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि भारत न केवल दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विविध और समावेशी आधुनिक लोकतंत्र की सीखों को सभी के साथ साझा करना चाहता है, बल्कि इसके साथ ही भारत की सभ्यतागत विरासत में गहराई से निहित लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को भी साझा करना चाहता है।

सम्पादकीय

सम्बंधों को और प्रगाढ़ कर रहे रणनीतिक साझेदार भारत-रूस

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसम्बर को भारतीय राजकीय दौरे पर आ रहे हैं। ये साल 2021 के बाद पहली बार होगा जब ब्लादिमीर पुतिन भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में होंगे। भारत और रूस के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। दोनों ही राष्ट्र कई अहम मौकों पर एक-दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस अतिरिक्त एस- 400 सिस्टम और सुखोई-57 लड़ावू विमानों को लेकर रक्षा समझौते पर बात आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रूस से कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी वार्ता हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा रूस और भारत को परमाणु ऊर्जा, तकनीक और कारोबार के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का मौका भी देगी। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चार साल बाद यह यात्रा हो रही है बल्कि इसलिए भी है कि लंबे समय से चले आ रहे वैश्विक संघर्ष और अमेरिकी टैरिफ के दबाव से खंडित हो रही वैश्विक भू-राजनीति में यह एक स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति के पक्ष में दोनों देशों का एक रणनीतिक दिशा भी तय कर सकती है। रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने रूस के सरकारी टीवी से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा पर जोर देते हुए कहा है कि ये यात्रा भव्य और कामयाब होगी। राष्ट्रपति पुतिन की ये भारत यात्रा भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का भी संकेत देती है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को अलग-थलग करने के पश्चिमी देशों के दबाव को भारत टालता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाए हैं और प्रतिबंध भी लगाए हैं जिससे अमेरिका और भारत के संबंधों पर भी इनका असर पड़ा है। विश्लेषक भी मान रहे हैं कि पुतिन की ये यात्रा भारत और रूस के रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकती है और वैश्विक सुरक्षा को एक नया आकार भी दे सकती है। भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं जो शीत युद्ध के समय से ही चले आ रहे हैं। भारत रूसी हथियारों के सबसे बड़े खरीददारों में से एक है और यह भी नहीं भूला जाना चाहिए कि रूसी एस- 400 एयर डिफेंस प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के लिए कितनी उपयोगी रही है। पूर्व राजनयिक मेजर जनरल (रिटायर्ड) मंजीत सिंह पुरी ने कहा, दुनिया के दो अहम देशों रूस और भारत का उच्चतम स्तर पर एक साथ आना खास तौर पर महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस से मिले हथियार खासकर एस-400 ने भारत के लिए अहम भूमिका निभाई। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस ने भारत को सस्ते तेल की आपूर्ति बताई जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को राहत मिली। भारत के वुल तेल आयात का 35 फीसदी रूस से होता है, लेकिन दो बड़ी रूसी तेल वंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत को भी इस खरीद में कमी लाने पर मजबूर किया है। लिहाजा ऊर्जा व्यापार के लिए एक स्थायी व स्थिर तंत्र को कायम करना भी इस मुलाकात में चर्चा का विषय हो सकता है, जिसकी अमेरिका पर नजर होगी। एक अमेरिकन विश्लेषक ने कहा कि भारत और रूस दोनों एक-दूसरे के करीब आए हैं क्योंकि दोनों ही अमेरिका से दबाव महसूस कर रहे है। चूंकि भारत-रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और इस वजह से हाल के महीनों में भारत ट्रंप प्रशासन के निशाने पर है। भारत और अमेरिका के संबंधों में आई गिरावट के बीच भारत का रूस की तरफ से खुलकर हाथ बढ़ाना हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। पुतिन की नई दिल्ली को इस यात्रा से भारत-रूस दोनों की तरफ से दुनिया को एक संदेश जरूर जाएगा कि दोनों के पास ही शक्तिशाली दोस्त हैं। भारत ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों में समायोजित होने के लिए राष्ट्रीय हितों व जरूरतों को वैश्विक साझेदारियों का आधार बनाया है। ऐसे वक्त में जब विश्व बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर अग्रसर है। भारत को रूस के साथ गहरा सहयोग न केवल आर्थिक, रक्षा व सामरिक हितों को मजबूत करेगा बल्कि पूरे विश्व को राजनीति पर असर डाल सकता है। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 33वीं बैठक

योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और किसान-केंद्रित हो- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह

छोटे किसानों को मिलें ज्यादा से ज्यादा लाभ, उनकी आय भी बढ़े- श्री शिवराज सिंह

बागवानी उत्पाद जल्दी खराब होने से बचाने के लिए रणनीति बनाएं, ताकि सेल्फ लाइफ बढ़े- श्री शिवराज सिंह

किसानों को नुकसान नहीं हो; अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं ठलइ- श्री शिवराज सिंह

(एजेंसी)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कृषि भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) के निदेशक मंडल की 33वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर भी उपस्थित थे।

फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा और रणनीति निर्धारण- बैठक में श्री शिवराज सिंह चौहान ने ठलइ की योजनाओं की समीक्षा की। विशेष रूप से वाणिज्यिक बागवानी विकास योजनाएं, कोल्ड-चेन अवसंरचना परियोजनाएं, क्लस्टर विकास कार्यक्रम (उउढ)- क्षेत्र-विशिष्ट बागवानी क्लस्टरों के माध्यम से उत्पादकता और बाजार जुड़ाव को बढ़ाने की नई पहल, क्लीन प्लांट कार्यक्रम-उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए रोग-मुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने निर्देश दिया कि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और किसान-केंद्रित हो तथा किसानों को सब्सिडी भी समय पर दी जाएं, इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। साथ ही, श्री शिवराज सिंह ने किसानों के हित में, जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के संबंध में विशेष रणनीति बनाने पर जोर दिया, ताकि इनकी सेल्फ लाइफ बढ़े, किसानों को नुकसान नहीं हो और नुकसान से बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाएं।

एनएचबी की भूमिका सुदृढ़ करने के लिए मार्गदर्शन- बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बागवानी क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु कई रणनीतिक सुझाव दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, फसलोत्तर प्रबंधन, उत्पादकता वृद्धि पर विशेष ध्यान देने को कहा। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि पूरे समन्वय के साथ किसानों को बाजार, कोल्ड-चेन नेटवर्क और मूल्य संवर्धन के अवसरों से जोड़ने वाली व्यवस्था को सुदृढ़ करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों के फायदे के लिए एनएचबी राज्यवार, क्षेत्रवार रोडमैप बनाकर पूरी ताकत से श्रेष्ठ कार्य करें।

तकनीकी प्रकाशनों का विमोचन- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा तैयार गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैविक खेती मॉडल और उन्नत बागवानी तकनीकों पर आधारित तकनीकी प्रकाशनों का विमोचन किया। ये संसाधन किसानों, उद्यमियों व कृषि विशेषज्ञों के लिए एक उपयोगी संदर्भ सामग्री सिद्ध होंगे। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगीलाल जाट सहित कृषि, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, बागवानी उद्योग से जुड़े गैर-आधिकारिक सदस्य उपस्थित रहे। इस व्यापक प्रतिनिधित्व से बैठक में क्षेत्रीय दृष्टिकोण व सहभागी संवाद को बल मिला। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो देशभर में वाणिज्यिक बागवानी और कोल्ड-चेन अवसंरचना के सुदृढ़ विकास के लिए कार्यरत है।

परफॉर्मेंस, सर्विस क्वालिटी और एक्सपीरियंस क्वालिटी पर आईटीयू-ट्राई कार्यशाला का उद्घाटन

(एजेंसी)।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) के साथ साझेदारी में आज भुवनेश्वर में परफॉर्मेंस, सर्विस क्वालिटी और एक्सपीरियंस क्वालिटी पर आईटीयू-ट्राई कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दो दिन के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में दुनिया भर के नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनआरएएस), सर्विस प्रोवाइडर और तकनीकी विशेषज्ञ एक साथ आए ताकि टेलीकॉम सर्विस-क्वालिटी फ्रेमवर्क पर मिलकर किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। कार्यशाला की शुरूआत एक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद ट्राई के सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार चौधरी ने स्वागत भाषण दिया और आईटीयू तथा ओडिशा सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ट्राई के चेयरमैन श्री अनिल कुमार लाहोटी ने उद्घाटन संबोधन किया।

अपने स्वागत भाषण में, श्री अतुल कुमार चौधरी ने पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित नियमन के लिए ट्राई की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। उन्होंने सेवा गुणवत्ता कार्यक्रम को मजबूत करने में वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कनेक्टिविटी मानचित्रण, उपग्रह-आधारित गुणवत्ता मूल्यांकन और क्षेत्रीय नियामक पहल पर चर्चा होने से सामूहिक समझ कायम करने में काफी मदद मिलेगी।

उद्घाटन सत्र के दौरान केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर का एक वीडियो संदेश साझा किया गया। उन्होंने नागरिकों के लिए भरोसेमंद और उच्च-गुणवत्ता पूर्ण कनेक्टिविटी पर भारत के फोकस के बारे में बताया, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत सर्विस क्वालिटी को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों से अवगत कराया और वैश्विक मानदंडों और सर्वश्रेष्ठ तौर-तरीकों को आगे बढ़ाने में ट्राई एवं आईटीयू के संयुक्त कार्यों का स्वागत किया।

इस सत्र में आईटीयू टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन ब्यूरो (आईटीयू-टीएसबी) के डायरेक्टर श्री सेइजो ओनो का एक वीडियो संदेश भी शामिल था। इस संदेश में उन्होंने इक्विटेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को इनेबल करने में हामोर्नाइज्ड क्यूओएस मानदंडों के वैश्विक महत्व के बारे में बताया। उन्होंने अलग-अलग देशों के लिए सही क्यूओएस और क्यूओई फ्रेमवर्क डिजाइन करने में सदस्य देशों को समर्थन करने के आईटीयू की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव, आईएएस श्री मनोज आहूजा ने लोगों की सुरक्षा और आपदा मोचन प्रणाली में दूरसंचार सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। चक्रवात और सुनामी अलर्ट के साथ ओडिशा के अनुभव से सीखते हुए, उन्होंने समावेशी विकास, आर्थिक विकास और प्रभावी लोक सेवा वितरण में दूरसंचार सेवा की मुख्य भूमिका पर जोर दिया। यह देखते हुए कि आज कल्याण से जुड़ी लगभग हर प्रणाली कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है, उन्होंने जोर दिया कि समय पर चेतावनी और समुचित सेवा वितरण के लिए मजबूत क्यूओएस और क्यूओई सिस्टम जरूरी हैं। उन्होंने कहा, 'आज दूरसंचार समावेशी विकास, आर्थिक विकास और हर बड़े कल्याण कार्यक्रम का लाभ पहुंचाने में आधार का काम करता है। ग्रामीण शासन और पंचायत सेवा के ऑनलाइन होने से लेकर सार्वजनिक कार्य के बेहतर कार्यान्वयन तक, कनेक्टिविटी अब रोजमर्रा के जीवन के हर पहलू को छूती है।' उन्होंने यह भी कहा कि

'उपभोक्ता-केंद्रित क्यूओएस पर लगातार फोकस, जिसे राज्यों और देशों के बीच समन्वय से समर्थन मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सभी के लिए सेवा गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है।'

उद्घाटन भाषण देते हुए, ट्राई के चेयरमैन श्री अनिल कुमार लाहोटी ने डिजिटल रूप से सबको साथ लेकर चलने वाला टेलीकॉम इकोसिस्टम बनाने में भारत की तरक्की और रोजमर्रा की जिंदगी में कनेक्टिविटी की बदलाव लाने वाली भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया भर में 5जी सेवा को सबसे तेजी से शुरू किया है, जिसे 1.23 बिलियन से अधिक दूरसंचार ग्राहक और लगभग 99 प्रतिशत 4जी कवरेज का समर्थन मिला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में डेटा की खपत का स्तर लगातार बढ़ रहा है, साथ ही सस्ते टैरिफ भी हैं जो सभी सामाजिक-आर्थिक समूह के लिए बड़ी डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

श्री लाहोटी ने शहरी-ग्रामीण अंतर को कम करने, मोबाइल-बेस्ड फाइनेंशियल इनक्लूजन को मुमकिन बनाने और दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रक्रियात्मक कार्यक्रम को आसान बनाने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारत के एक मॉडल के तौर पर उभरने पर जोर दिया। उन्होंने भवनों के लिए ट्राई के सेवा गुणवत्ता रेटिंग कार्यक्रम को सेवा गुणवत्ता मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक जरूरी पहल बताया और भवनों के अंदर होने वाले डेटा इस्तेमाल के बड़े हिस्से को देखते हुए इनडोर कनेक्टिविटी को मजबूत करने की बढ़ती जरूरत पर ध्यान केंद्रित किया।

इसके बाद उन्होंने गहरे मल्टीलेटरल कोलेबोरेशन की जरूरत पर जोर दिया और धोखाधड़ी की रोकथाम, साइबर सुरक्षा और नेटवर्क इंटरऑपरेबिलिटी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्यूओएस और क्यूओई पर एशिया के लिए एक आईटीयू रीजनल ग्रुप बनाने की मांग की। उन्होंने कहा, 'भारत का अनुभव दिखाता है कि कैसे व्यापक दूरसंचार नीति, नियामक सुधार और मजबूत सहयोग समावेशी विकास और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।' उन्होंने कहा कि समन्वित क्षेत्रीय प्रयासों से पूरे एशिया में क्यूओएस और क्यूओई फ्रेमवर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

पहले सेशन के आखिर में, आईटीयू के स्टडी ग्रुप एडवाइजर मिस्टर मार्टिन एडॉल्फ ने कार्यशाला आयोजित करने के लिए ट्राई और समर्थन के लिए ओडिशा सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों के योगदान को स्वीकार करते हुए कहा कि ये चर्चाएं सीधे तौर पर क्यूएसडीजी के ग्लोबल क्यूओएस और क्यूओई फ्रेमवर्क को मजबूत करने के भविष्य के काम के बारे में बताएंगी।

वर्कशॉप में 4 दिसंबर को चार विषय आधारित सत्र हैं, जिसमें कनेक्टिविटी मानचित्रण, उपग्रह सेवा निष्पादन, मापन विधि और पूरे एशिया में सेवा गुणवत्ता पहल पर एक क्षेत्रीय पैनल शामिल है। इन सेशन में रेगुलेटर, इंडस्ट्री लीडर और एक्सपर्ट टूल, मेथड और रेगुलेटरी नजरिए का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ आए। 5 दिसंबर को, प्रोग्राम क्वालिटी ऑफ सर्विस डेवलपमेंट ग्रुप (क्यूएसडीजी) की मीटिंग के साथ जारी रहेगा, जिसके बाद आईटीयू-टी स्टडी ग्रुप 12 की 'एनआरए रिपॉजिटरी' पहल पर एक रैपॉर्टर ग्रुप मीटिंग होगी, जिसका मकसद रेगुलेटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्यूओएस और क्यूओई पैरामीटर की एक ग्लोबल लाइब्रेरी बनाना है।

वर्कशॉप का मकसद क्यूओएस और क्यूओई मैनेजमेंट में मुख्य

भारत भर में सभी डाक घर आपीपीबी सेवा प्रदान करते हैं और आईपीपीबी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) से जुड़े हैं

घर पर बैंकिंग सेवा देने के लिए सभी पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरण दिए गए हैं

(एजेंसी)।

आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत, डाक विभाग (डीओपी) ने अत्याधुनिक डाक प्रौद्योगिकी (एपीटी) प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक शुरू किया है। यह एक स्वदेशी, क्लाउड-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र (सीईपीटी) ने आंतरिक स्रोतों की मदद से विकसित किया है और मेघराज 2.0 क्लाउड पर होस्ट किया है। एपीटी ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने के लिए तेज और स्केलेबल है और इसे 4 अगस्त 2025 को पूरे देश में शुरू किया गया है, जिसमें 23 डाक सर्कल के लगभग 1.70 लाख कार्यालय शामिल हैं। ब्रांच पोस्ट ऑफिस को भी इन-हाउस डिजिटल रूरल एंटरप्राइज एप्लीकेशन फॉर मोबाइल (ड्रीम) ऐप चलाने वाले एंड्रॉयड स्मार्टफोन दिए गए हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में सर्विस डिलीवरी, बेहतर कनेक्टिविटी और उपयोगकर्ताओं के अनुभवों को और मजबूत किया जा सके। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत, 25022 डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

सभी पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को घर-घर बैंकिंग सर्विस देने के लिए स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरण दिए गए हैं। डीओपी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के जरिए अपनी वित्तीय सेवा बढ़ाई हैं, जैसे अकाउंट खोलना, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी), थर्ड-पार्टी के जरिए बीमा सेवा, डाक घर बचत खाते, क्रेडिट रेफरल सुविधा, किसी भी नागरिक के लिए आधार में मोबाइल नंबर अपडेट और 5 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के लिए चाइल्ड आधार एनरोलमेंट सर्विस। पूरे भारत में सभी डाक घर आईपीपीबी सेवा देते हैं और आईपीपीबी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) से जुड़े हैं।

लॉजिस्टिक्स संगठनों के रूप में डाक घर

डाक विभाग ने गति, भरोसा और ग्राहकों के अनुभव बेहतर बनाने के लिए पार्सल प्रोसेसिंग और डिलीवरी इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने जैसे जरूरी कदम उठाए

डाक विभाग ने एक बड़े पब्लिक लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलाव लाने और देश भर में अपनी पार्सल सेवाओं को मजबूत करने के लिए अनेक पहल की हैं। मुख्य उपायों में देश भर में स्टैंडर्ड सिस्टम के जरिए स्पीड, भरोसा और उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पार्सल प्रोसेसिंग और डिलीवरी इकोसिस्टम को मॉडर्न बनाना शामिल है। मैकेनाइज्ड और डेडिकेटेड पार्सल डिलीवरी के लिए नोडल डिलीवरी सेंटर के साथ लास्ट-माइल डिलीवरी को बेहतर बनाया गया है। एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (एपीटी) 2.0 प्रोजेक्ट के तहत, रियल-टाइम डिलीवरी अपडेट, ओटीपी-बेस्ड डिलीवरी और ई-कॉमर्स और दूसरे कस्टमर्स के साथ एपीआई इंटीग्रेशन शुरू किया गया है। मेल और पार्सल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट (एमपीओपी) के तहत ऑटोमेशन, स्टैंडर्ड वर्कफ़्लो और पार्सल सॉर्टर और रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए एंड-टू-एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। विभाग बड़ी ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ भी साझेदारी कर रहा है और पार्सल डिलीवरी के लिए एमएसएमई मंत्रालय समेत कई सरकारी मंत्रालयों को सर्विस दे रहा है। इसके अलावा, एमएसएमई, कारीगरों, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स और छोटे बिजनेस, खासकर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए 1,013 डाक घर निर्यात केंद्र (डीजीएनके) बनाए गए हैं।

यह बदलाव एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और मेल पार्सल ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत सुझावों के आधार पर इसे फेज में लागू किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने 'नो यूअर डिजीपिन' एप्लिकेशन शुरू किया है। यह नेशनल डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की बेसिक लेयर है।

एड्रेस-एज-ए-सर्विस (एएएएस) - एड्रेस डेटा मैनेजमेंट से जुड़ी सर्विसेज की रेंज - के लिए एक डीपीआई विकसित करने के लिए, डिपार्टमेंट ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम 'ध्रुव' को फाइनल किया है, जिसका मकसद एड्रेस इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को एक बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर पहचान देना है, जो असरदार गवर्नेंस, सबको साथ लेकर चलने वाली सर्विस डिलीवरी और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है।

यह जानकारी केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में दी।

राष्ट्रीय संचार अकादमी-वित्त (एनसीए-एफ) दिव्यांगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में पर्पल फेस्ट-2025 मनाया

(एजेंसी)।

दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक 'सर्वोत्कृष्ट' 5 स्टार-रेटेड केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय संचार अकादमी-वित्त (एनसीए-एफ), घिटोरनी ने दिव्यांगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में, दिव्यांगों के सशक्तीकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के सहयोग से 3 दिसंबर, 2025 को बड़े उत्साह के साथ पर्पल फेस्ट-2025 मनाया।

इस उत्सव का उद्घाटन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की सचिव सुश्री वी. विद्यावती ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में समाज को अधिक समावेशी बनाने के लिए आवश्यक मानसिक बाधाओं को दूर करने को कहा। राष्ट्रीय संचार अकादमी-वित्त की महानिदेशक ने सभी प्रतिभागियों को समावेशी शिक्षा, करुणा और सशक्तीकरण के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उप मुख्य आयुक्त सहित दिव्यांगों के सशक्तीकरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने अपने मार्गदर्शन और उत्साहवर्धक शब्दों से इस अवसर को समृद्ध बनाया।

कार्यक्रम में कई विचारपूर्वक गतिविधियां शामिल थी, जिसमें सुश्री इरा सिंघल, आईएएस का प्रेरक

संबोधन, गैर सरकारी संगठनों द्वारा व्यावहारिक सत्र और आकर्षक अनुभव और सहानुभूति एवं पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए कई समावेशी कार्यक्रम शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के सहयोग से राष्ट्रीय संचार अकादमी-वित्त में विशेष फाउंडेशन कोर्स कर रहे 15 अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवाओं के वर्ष 2025 बैच के 176 अधिकारी प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय संचार अकादमी-वित्त के संकाय और कर्मचारियों के साथ समारोह में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।

राष्ट्रीय संचार अकादमी-वित्त के संकाय सदस्यों के लिए दिव्यांगजनों के उप मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) सत्र आयोजित किया गया। साथ ही, संवेदीकरण और जागरूकता निर्माण के उद्देश्य से सिमुलेशन गतिविधियों की एक श्रृंखला भी आयोजित की गई।

दिव्यांगजन उद्यमियों, जिनमें बच्चे और युवा भी शामिल थे, द्वारा लगाए गए स्टॉल और प्रदर्शनियों के जीवंत प्रदर्शन को अतिथियों, एनसीए-एफ कर्मचारियों, प्रशिक्षु अधिकारियों, निवासियों और आगंतुकों से उत्साहपूर्वक प्रशंसा प्राप्त किया। उनकी भागीदारी ने उद्यमियों और रचनाकारों को दृश्यता, पहचान और वित्तीय सशक्तीकरण के अवसर प्रदान किए।

पर्पल फेस्ट-2025 प्रतिभा, लचीलेपन और आकांक्षा के उत्सव के रूप में सामने आया, जिसमें समावेशिता की भावना और एक सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण की साझा जिम्मेदारी का सम्मान किया गया।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

तत्काल बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संशोधन लागू

मुंबई,

पश्चिम रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, तत्काल बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संशोधन लागू किया जा रहा है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो यात्री द्वारा बुकिंग के समय प्रदान किया गया है, और ओटीपी के सफल सत्यापन के बाद ही टिकट जारी किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ओटीपी-आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली को प्रारंभिक रूप से 01 दिसंबर 2025 से ट्रेन संख्या 12009/12010 मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस में लागू किया गया था। अब यह ओटीपी-आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली 05 दिसंबर 2025 से निम्नलिखित ट्रेनों में भी लागू की जा रही है:

ट्रेन संख्या 12227/12228 मुंबई सेंट्रल - इंदौर दुरंतो एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12239 मुंबई सेंट्रल - हिसार दुरंतो एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12267/12268 मुंबई सेंट्रल - हापा दुरंतो एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12297 अहमदाबाद - पुणे दुरंतो एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12462 साबरमती - जोधपुर वंदे भारत

ट्रेन संख्या 12951 मुंबई सेंट्रल झ नई दिल्ली राजधानी तेजस

ट्रेन संख्या 12953 मुंबई सेंट्रल झ हजरत निजामुद्दीन ए.के. राजधानी तेजस एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12957 साबरमती झ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस

नई प्रणाली कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली सभी तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। इस बदलाव का उद्देश्य तत्काल बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना तथा वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में बेहतर सुविधा प्रदान करना है।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे बुकिंग के समय वैध मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध कराएँ, ताकि ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पश्चिम रेलवे द्वारा सभी यात्रियों से इस महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

बनास डेयरी का क्षेत्रीय दौरा करेंगे श्री अमित शाह तथा सांसदगण

सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति दौरे के दौरान 'सहकारी डेयरी विकास' से संबंधित प्रगति की समीक्षा करेगी

श्री अमित शाह बायो-सीएनजी एवं उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे तथा पाउडर एवं बेबी फूड संयंत्र का भूमिपूजन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारी आंदोलन देशभर में ग्रामीण समृद्धि, मूल्य संवर्धन और सतत विकास का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है

इस दौरे का उद्देश्य, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि पर आधारित और श्री अमित शाह के नेतृत्व में क्रियान्वित 'सहकारी मॉडल' द्वारा 'सहकार से समृद्धि' तथा 'विकसित भारत' के लक्ष्यों की प्राप्ति में किये जा रहे योगदान को दशार्ना है

(एजेंसी)।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति डेयरी विकास, परिपत्र अर्थव्यवस्था, कृषि मूल्य संवर्धन, पशुधन उत्पादकता, जल संरक्षण तथा

ग्रामीण सहकारिता सशक्तीकरण के क्षेत्रों में बनास डेयरी द्वारा की गई विविध पहलों की समीक्षा करेगा। 4 से 6 दिसंबर 2025, तक बनासकांठा स्थित बनास डेयरी का क्षेत्रीय दौरा यह भी प्रदर्शित करेगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर आधारित और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मंत्रालय के माध्यम से लागू सहकारी मॉडल 'सहकार से समृद्धि' तथा 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्यों को कैसे सार्थक रूप से आगे बढ़ा रहा है। सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर एवं श्री मुरलीधर मोहोळ, सहकारिता मंत्रालय के सचिव तथा सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की तीसरी बैठक, 6 दिसंबर 2025 को बनासकांठा स्थित बनास डेयरी परिसर में आयोजित होगी जिसमें 'सहकारी डेयरी विकास' से संबंधित विभिन्न पहलों की समीक्षा की जाएगी।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरे में भाग लेंगे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक 3 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया की अध्यक्षता में संसदीय सौध भवन में हुई। बैठक में केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री सुकांत मजूमदार भी शामिल हुए।

श्री सिंधिया ने लोकसभा और राज्यसभा की समिति के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समिति की बैठकें पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश और विकास प्रगति पर निरंतर संवाद का एक अभिन्न अंग हैं। उन्होंने परामर्शदात्री समिति की बैठकों के

दौरान सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए उनका धन्यवाद भी किया।

पीएम-डिवाइन (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल) को मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण योजना बताते हुए, श्री सिंधिया ने बताया कि इस योजना की परिकल्पना केंद्रीय बजट वर्ष 2022-2023 में की गई थी। इस योजना का वर्ष 2022-2023 से 2025-2026 की अवधि के लिए कुल परिव्यय 6600 करोड़ रुपये है। 31 अक्टूबर, 2025 तक लगभग 5,700 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। लगभग 176 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजनाओं में से तीन पूरी हो चुकी हैं और लगभग 5,500 करोड़ रुपये की 41 परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। इसके अलावा, 111 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है और 625 करोड़ रुपये की और परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। मंत्रालय योजना परिव्यय का पूरा उपयोग करने की दिशा में अग्रसर है।

समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने असम, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं का विशिष्ट विवरण प्रदान किया। त्रिपुरा में पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए एक सुझाव पर मंत्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकारों के परामर्श से चिन्हित चयनित स्थानों पर, प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में विश्व-स्तरीय सुविधाओं के साथ पर्यटन सर्किट विकसित किए जाएंगे। शुरूआत में, मेघालय में सोहरा सर्किट और त्रिपुरा में माताबारी सर्किट को पायलट आधार पर लिया जा रहा है। मेघालय-सोहरा सर्किट की आधारशिला पहले ही रखी जा चुकी है जबकि त्रिपुरा-माताबारी सर्किट अनुमोदन के अंतिम चरण में है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा पर्यटन सर्किट परियोजना में पर्यटन में वृद्धि और बेहतर पर्यटक अनुभव के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण पर मजबूत ध्यान दिया जाएगा।

एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मेंटेनेंस कमांड एयर मार्शल यल्ला उमेश ने बेस रिपेयर डिपो तुगलकाबाद का दौरा किया

(एजेंसी)।

एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मेंटेनेंस कमांड, एयर मार्शल यल्ला उमेश, ने आज 04 दिसंबर 2025 को बेस रिपेयर डिपो, तुगलकाबाद का दौरा किया। उनके साथ क्षेत्रीय वायु सेना परिवार कल्याण संघ की अध्यक्ष श्रीमती श्रीवल्ली भी थीं। वायु सेना स्टेशन तुगलकाबाद के एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयर कमोडोर डीएन साहू और एएफएफडब्ल्यूए की स्थानीय अध्यक्ष श्रीमती प्रीति साहू ने उनका स्वागत किया।

एयर मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके उपरांत उन्हें डिपो के कामकाज, नवोन्मेष, उपलब्धियों और जारी पहल से अवगत कराया गया। एयर मार्शल यल्ला उमेश ने विभिन्न अनुभागों में पहुंचकर परियोजनाओं की समीक्षा की और परिचालन आवश्यकता अनुरूप स्वदेशीकरण और नवीन समाधानों के डिपो के प्रयासों की सराहना की।

स्टेशन कर्मियों के साथ संवाद में एयर मार्शल ने आयात पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी क्षमता सुदृढ़ कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय इकाइयों को उन्नत तकनीकी और परिचालन सहायता सुनिश्चित करने में सभी कर्मियों की भागीदारी, समर्पण और पेशेवर रुख की सराहना की।

एयर मार्शल यल्ला उमेश ने तकनीकी कौशल और बेहतर बनाने, सभी भूमिकाओं में दक्षता और उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने की आवश्यकता भी रेखांकित की। एयर मार्शल ने सभी वायु योद्धाओं से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और चुस्त रहने का आ'ान किया ताकि परिचालन तत्परता और उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति सजगता बनी रहे।

चांदी के आभूषणों के लिए अनिवार्य एचयूआईडी पर अपडेट, शुद्धता की गारंटी और नकली हॉलमार्किंग पर रोक लगाने में एक महत्वपूर्ण कदम

(एजेंसी)।

चांदी के लिए अनिवार्य एचयूआईडी लागू होने के बाद पहले तीन महीनों के भीतर, 17 लाख से ज्यादा चांदी की हॉलमार्किंग की जा चुकी है, जो ज्वैलर्स और उपभोक्ताओं के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दशार्ता है। हालाँकि चांदी हॉलमार्किंग योजना स्वैच्छिक बनी हुई है, फिर भी हॉलमार्क वाली किसी भी चांदी की वस्तु के लिए एचयूआईडी मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है ।

मजबूत रुझान: 17 लाख से अधिक वस्तुओं को पहले ही एचयूआईडी के साथ हॉलमार्क किया जा चुका है

सिल्वर एचयूआईडी पोर्टल की शुरूआत के बाद से, यानी तीन महीनों के भीतर, 17 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा चुकी है। शुद्धता ग्रेड 925 और 800, सभी हॉलमार्क वस्तुओं का लगभग 90% हिस्सा हैं। एचयूआईडी की शुरूआत के बाद इसमें उल्लेखनीय तेजी देखी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में, लगभग 32 लाख चांदी की वस्तुओं की हॉलमार्किंग की गई। यह उछाल एचयूआईडी प्रणाली में उपभोक्ताओं और ज्वैलर्स के मजबूत विश्वास को दशार्ता है।

चांदी की हॉलमार्किंग के ट्रेंड्स दशार्ते हैं कि देश का दक्षिणी क्षेत्र हॉलमार्किंग के मामले में सबसे आगे है, उसके बाद पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र का स्थान है। उत्पाद श्रेणियों में, पायल/ एंकलेट की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और ये मुख्य रूप से 800 शुद्धता ग्रेड में हॉलमार्क की जाती हैं। इसके बाद चांदी के दीये आते हैं, जो आमतौर पर 800 और 925 शुद्धता ग्रेड में होते हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर बताया कि - "चांदी के आभूषणों में हॉलमार्किंग में एचयूआईडी शुद्धता आश्वासन को मजबूत करने और नकली हॉलमार्किंग प्रथाओं को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वैच्छिक (बीआईएस) हॉलमार्क वाली चांदी की वस्तुओं पर एचयूआईडी अनिवार्य होने के साथ, प्रत्येक आभूषण पर एक विशिष्ट 6-अंकीय पहचान कोड होता है जो पूर्ण डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और बेहतर उपभोक्ता संरक्षण को सक्षम बनाता है। एचयूआईडी प्रणाली के तहत पहले से ही 17.35 लाख से अधिक वस्तुओं की हॉलमार्किंग की जा चुकी है, यह पहल उपभोक्ताओं और हितधारकों के बीच अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास पैदा कर रही है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 1 सितंबर 2025 से चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) लागू करने की घोषणा की है, जो उपभोक्ता संरक्षण, शुद्धता आश्वासन को मजबूत करने और नकली हॉलमार्किंग को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है ।

एचयूआईडी क्या है? एचयूआईडी एक छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है जो प्रत्येक हॉलमार्क वाली चांदी की वस्तु पर लेजर से अंकित होता है, साथ ही बीआईएस मानक चिह्न, शब्द रक्छएएफ और शुद्धता ग्रेड भी अंकित होता है। यह विशिष्ट पहचानकर्ता प्रत्येक हॉलमार्क वाली चांदी की वस्तु की पूरी डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्रदान करता है, जिससे चांदी की हॉलमार्किंग, सोने के लिए मौजूदा एचयूआईडी-आधारित हॉलमार्किंग प्रणाली के समकक्ष हो जाती है।

बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से सत्यापन आसान हुआ

उपभोक्ता बीआईएस केयर मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध) पर एचयूआईडी दर्ज करके हॉलमार्क वाले चांदी के आभूषणों की प्रामाणिकता तुरंत सत्यापित कर सकते हैं। ऐप में निम्नलिखित प्रमुख विवरण प्रदर्शित होते हैं:

आभूषण की शुद्धता

आभूषण का प्रकार (अंगूठी, पायल, चेन, आदि)

हॉलमार्किंग के लिए आभूषण प्रस्तुत करने वाले जौहरी का विवरण

परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र का विवरण

यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र

वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित 'काशी तमिल संगमम् 4.0' में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी के तीसरे दिन हजारों की संख्या में छात्र-छात्राओं, तमिलनाडु से आये हुए डेलिगेट्स एवं आम लोगों द्वारा प्रदर्शनी का किया गया अवलोकन

'काशी तमिल संगमम् 4.0' में तमिलनाडु से आये हुए डेलिगेट्स ने केंद्रीय संचार ब्यूरो की चित्र प्रदर्शनी को सराहा, कहां चित्र प्रदर्शनी में काशी एवं तमिल की विभूतियों का है अद्भुत संगम

प्रदर्शनी में चित्र प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, विजेता छात्र-छात्राओं को केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा किया गया पुरस्कृत

प्रदर्शनी को डिजिटल रूप में भी किया गया है प्रदर्शित, जिसके माध्यम से 'काशी तमिल संगमम 4.0' के साथ साथ केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां एवं सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को दशार्या जा रहा है

(एजेंसी)।

वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित 'काशी तमिल संगमम्-4.0' में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रदर्शनी के तीसरे दिन आज हजारों की संख्या में स्कूलों से आये हुए छात्र - छात्राओं, तमिलनाडु से आए हुए डेलिगेट्स तथा स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम् में आये हुए डेलिगेट्स द्वारा प्रदर्शनी की

सराहना की गई। उन्होंने कहा कि इस चित्र प्रदर्शनी में काशी और तमिलनाडु की महान विभूतियों का अद्भुत संगम है।

केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा प्रदर्शनी देखने आये हुए स्कूलों के छात्र - छात्राओं के बीच चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा विजेता छात्र - छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने वाले 'काशी तमिल संगमम्' के इस चतुर्थ संस्करण में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगायी गयी चित्र प्रदर्शनी में तमिलनाडु एवं काशी की महान विभूतियों के राष्ट्र निर्माण में योगदान एवं उनकी उपलब्धियां को दशार्या गया है। चित्र प्रदर्शनी में तमिलनाडु की महान विभूतियों जैसे ऋषि अगस्त्य, तमिल महिला कवि संत अव्वैयार, तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर, कवयित्री और संत कारैकल अम्माइयार, भक्ति आंदोलन की कवि एवं संत अंडाल (कोधाई), थिरूनावुक्कारसर, तमिल कवि और समाज सुधारक श्री रामलिंग स्वामी (वल्लालार), तमिल विद्वान यू. वी. स्वामीनाथ अय्यर, अग्रणी समाज सुधारक, चिकित्सक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ब्रिटिश भारत में पहली महिला विधायक डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी, गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन, अविष्कारक और उद्योगपति जी.डी. नायडू, खगोलशास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, नोवेल पुरस्कार विजेता वेंकटरामन रामकृष्णन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नोबेल पुरस्कार विजेता एवं महान वैज्ञानिक चंदशेखर वेंकट रमन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सुप्रसिद्ध राजनेता एवं भारत रत्न के. कामराज, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सुप्रसिद्ध राजनेता चिदंबरम सुब्रमण्यम, महान अभिनेता एवं राजनेता एम. जी. रामचंद्रन इत्यादि के जीवन दर्शन को चित्रों एवं शब्दों में दशार्या गया है।

इसी प्रकार काशी की महान विभूतियां जैसे - संत कबीरदास, संत रविदास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय, सुप्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार पंडित रविशंकर, महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद इत्यादि के जीवन दर्शन को चित्रों शब्दों के माध्यम से दशार्या गया है।

चित्र प्रदर्शनी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किये जा रहे सरकार के जन कल्याणकारी नीतियों, प्रयासों एवं योजनाओं को भी दशार्या गया है। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हाल में श्रम सुधार के लिए बनाये गये कानूनो, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी के दरों को कम करने के लिये किए गये प्रयासों की जानकारी दर्शकों और जनसामान्य के लिए प्रदर्शित की गई है। चित्र प्रदर्शनी को डिजिटल रूप में भी प्रदर्शित किया गया है, जिसमें काशी तमिल संगमम के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ केंद्र सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों, जीएसटी के दरों में की गई कमी, नये श्रम संहिता के बारे में भी लोगों को जानकारी प्रदान की जा रही है। प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार वाराणसी शहर में आ.ई.सी. वैन के माध्यम से भी किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 15 दिसंबर तक निरंतर रहेगी।

मेरा गाँव मेरी धरोहर योजना के तहत 6.38 लाख गाँव की सांस्कृतिक मानचित्रण किया गया

(एजेंसी)।

देश भर में सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर (एमजीएमडी) कार्यक्रम के तहत पहचाने गए गांवों की संख्या 6,38,365 है, जिनमें से अब तक 6,23,449 गांवों का डेटा एमजीएमडी पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

अपने दस्तावेजीकरण कार्यों के तहत, एमजीएमडी, सांस्कृतिक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है, जिसमें मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के तत्व शामिल हैं, जिनमें मौखिक परंपराएं, विश्वास, रीति-रिवाज, ऐतिहासिक महत्व, कला के रूप, विरासत स्थल, पारंपरिक भोजन, प्रमुख कलाकार, मेले और त्यौहार, पारंपरिक पोशाक, आभूषण और

स्थानीय स्थल शामिल हैं।

एमजीएमडी कार्यक्रम स्थानीय परंपराओं, प्रथाओं और विरासत संपदाओं को मान्यता प्रदान करने वाले प्रामाणिक, ग्राम-स्तरीय सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करके ग्रामीण पहचान को सुदृढ़ करता है। यह एमजीएमडी पोर्टल के माध्यम से समुदाय-आधारित दस्तावेजीकरण और जन-आधारित सत्यापन को सक्षम करके सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। एक ही राष्ट्रीय पोर्टल पर संरचित सांस्कृतिक डेटा की उपलब्धता सांस्कृतिक क्लस्टर विकास, विरासत पर्यटन और पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने की योजना बनाने में सहायक होती है, जिससे सतत आजीविका सृजन और ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान मिलता है।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

एएसआई ने राष्ट्रीय महत्व के 3,685 प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और रखरखाव का कार्य शुरू किया

राष्ट्रीय संस्कृति कोष (एनसीएफ) का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाना है

(एजेंसी)।

1976 से अब तक विदेशों से कुल 655 पुरावशेष प्राप्त किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) देश भर में राष्ट्रीय महत्व के 3,685 प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और रखरखाव का कार्य करता है, जिसमें पेयजल, शौचालय, रास्ते और भू निर्माण जैसी सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। इन स्मारकों और स्थलों का रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है और इसे आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

2007 में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन ने 11,406 निर्मित धरोहरों एवं स्थलों, तथा 12,46,211 पुरावशेषों से संबंधित आँकड़े संकलित एवं प्रकाशित किए हैं। ये आँकड़े एनएमएमए की वेबसाइट ६६६.ल्लें.ल्ल्रू.ल्ल पर प्रकाशित किए गए हैं।

सरकार ने 1996 में चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति कोष (एनसीएफ) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और विकास तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत के समग्र संवर्धन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाना था।

एनसीएफ में योगदान करते समय, कोई भी दाता/प्रायोजक किसी भी स्मारक के संरक्षण या उसके आसपास सुविधाओं के विकास हेतु किसी परियोजना का उल्लेख कर सकता है। संरक्षित स्मारकों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किया जाता है और उसका रखरखाव भी वही करता है। सभी दाता एजेंसियाँ एनसीएफ और एएसआई द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करती हैं।

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए पीपीपी मोड के तहत एनसीएफ द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी एएसआई, दाता और एनसीएफ को शामिल करते हुए परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या गैर-लाभकारी संगठनों सहित किसी भी निजी पार्टी को अनुमति देने के लिए कोई पायलट परियोजना शुरू नहीं की गई है।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर सभी वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी

(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर चीता की सुरक्षा के लिए समर्पित सभी वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणवादियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा, "तीन वर्ष पूर्व हमारी सरकार ने इस अद्भुत पशु की सुरक्षा और उस इकोसिस्टम को बहाल करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट चीता की शुरूआत की थी जिसमें यह वास्तविक रूप से फल-फूल सके। यह खोई हुई पारिस्थितिक विरासत को पुनर्जीवित करने और हमारी जैव विविधता को सुदृढ़ करने का भी एक प्रयास था।"

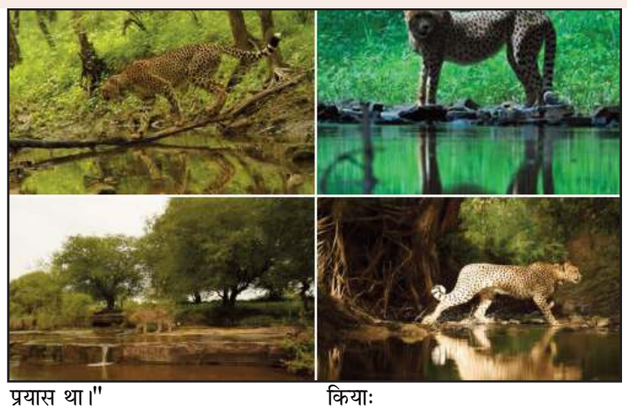

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया: "अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर हमारी पृथ्वी के सबसे अद्भुत जीवों में से एक चीता की सुरक्षा के लिए समर्पित सभी वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणवादियों को मेरी शुभकामनाएं। तीन साल पहले, हमारी सरकार ने इस अद्भुत जानवर की सुरक्षा और उस इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट चीता शुरू किया था जिसमें यह वास्तव में फल-फूल सके। यह खोई हुई पारिस्थितिक विरासत को पुनर्जीवित करने और हमारी जैव विविधता को सुदृढ़ करने का भी एक प्रयास था।"

पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(एजेंसी)।

वायु प्रदूषण के लिए कई कारक सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के उच्च-घनत्व वाले आबादी वाले क्षेत्रों में मानवजनित गतिविधियों का उच्च स्तर शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाहनों से होने वाला प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं से उत्पन्न धूल, सड़क और खुले क्षेत्रों की धूल, बायोमास जलाना, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट जलाना, लैंडफिल में आग लगना, बिखरे हुए स्रोतों से वायु प्रदूषण आदि के साथ-साथ विभिन्न मौसम संबंधी कारकों से उत्पन्न होता है। पराली जलाने को एक ऐसी घटना के रूप में पहचाना गया है जो वायु गुणवत्ता सूचकांक को बढ़ा देती है।

धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने और फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन पर एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की गई है।

इस योजना के तहत, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और उद्यमी के रूप में किसान), किसानों की सहकारी समितियों (कृषि/बागवानी/मखाना आदि), डे-एनआरएलएम क्लस्टर स्तरीय संघों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 80% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

धान आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं को उच्च एचपी ट्रैक्टर, कटर, टेडर, मध्यम से बड़े बेलर, रेकर, लोडर, ग्रैबर और टेली हैंडलर जैसी मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर 65% (अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये तक) की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

राज्यों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को फसल अवशेष प्रबंधन पर किसानों में व्यापक जागरूकता लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ चलाने हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। यह योजना फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आईसीएआर द्वारा अनुशंसित मशीनों और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देती है, चाहे वे फसल अवशेष प्रबंधन के साथ-साथ स्थानीय उपयोग के लिए भी हों।

2018-19 से 2025-26 (27.11.2025 तक) की अवधि के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 4,090.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। किसानों को 3.45 लाख से अधिक फसल अवशेष मशीनें (सीआरएम) प्रदान की गई हैं और इन राज्यों में 43,270 से अधिक कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसी) स्थापित किए गए हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टोरीफिकेशन संयंत्रों की स्थापना के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पेलेटाइजेशन संयंत्र की स्थापना के मामले में, 28 लाख रुपये प्रति टन प्रति घंटा (टीपीएच), या 1 टीपीएच संयंत्र और मशीनरी के लिए विचार की गई पूंजीगत लागत का 40%, जो भी कम हो, प्रति प्रस्ताव 1.4 करोड़ रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता के साथ प्रदान किया जाता है। टोरीफिकेशन संयंत्रों की स्थापना के मामले में, 56 लाख रुपये प्रति टीपीएच, या 1 टीपीएच संयंत्र और मशीनरी के लिए विचार की गई पूंजीगत लागत का 40%, जो भी कम हो, प्रति प्रस्ताव 2.8 करोड़ रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता के साथ प्रदान किया जाता है।

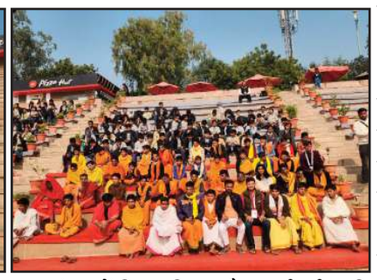

विद्युत मंत्रालय ने कृषि पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग हेतु राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास पेलेट्स के सह-प्रज्वलन हेतु एक व्यापक नीति 7 नवंबर, 2025 को जारी की गई है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्टों और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट से बायोगैस, बायो-सीएनजी/संवर्धित बायोगैस/ कंप्रेस्ड बायोगैस, बिजली/प्रोड्यूसर या सिंथेटिक गैस उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है :

प्रयागराज में काशी तमिल संगमम्‌ 4.0 के छात्र प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत; सभी ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम पर अध्यात्म की डुबकी लगायी

(एजेंसी)।

काशी तमिल संगमम्‌ 4.0 के अंतर्गत आए कुल 200 छात्रों का समूह आज काशी से प्रयागराज पहुंचा। यह समूह प्रातः 8:10 बजे विशेष बसों के माध्यम से काशी से प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व ऐतिहासिक एकता को और अधिक सुदृढ़ करना है एवं 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को नई ऊर्जा प्रदान करना है। लगभग 12 बजे यह दल संगम तट पहुँचा, जहाँ पारंपरिक शैली में उनका शानदार स्वागत किया गया। स्वागतकर्ताओं में प्रमुख रूप से महापौर श्री उमेश चंद्र गणेश केशवानी, सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह, मंडलीय सूचना अधिकारी इंद्रमणि पाण्डेय, सह जिला विद्यालय निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह, नगर निगम के जोनल अधिकारी संजय ममगई, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सुदेश शर्मा, एसीपी झूसी विमल किशोर मिश्रा तथा उपनिरीक्षक

नीरज मिश्रा उपस्थित रहे।

छात्रों के स्वागत के पश्चात उन्हें तमिल भाषा में प्रकाशित भागवत गीता की प्रति सम्मानपूर्वक प्रदान की गई, जिससे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदानझ्रप्रदान की यह यात्रा और भी अर्थपूर्ण बन सकी। संगम तट पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में दक्षिण और उत्तर भारत की विविध कला शैलियों ने एक अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। करगम, कावड़ी, मरकलाअट्टम जैसी तमिल लोक कलाओं के साथ कजरी, भजन और कथक की प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। 'कला के माध्यम से एकता' का यह दृश्य उपस्थित सभी लोगों के लिए यादगार बन गया।

काशी तमिल संगमम 4.0 का तीसरे दिन तमिलनाडु से आये छात्रों ने आज प्रयागराज में संगम से नौका भ्रमण किया। सभी ने

गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम पर अध्यात्म की डुबकी लगायी।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद छात्रों को दो समूहों में विभाजित कर पवित्र संगम स्नान हेतु ले जाया गया। वहाँ छात्रों ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम की दिव्यता को आत्मसात किया। आध्यात्मिक अनुभूति से ओत-प्रोत इस क्रम के बाद सभी को श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन कराने ले जाया गया, जहाँ उन्होंने श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की। इसके उपरांत छात्र दल स्वामीनारायण मंदिर पहुँचा, जहाँ सभी ने प्रसाद स्वरूप भोज ग्रहण किया। पूरे दिन छात्रों ने प्रयागराज की ऐतिहासिक समृद्धि, आस्था और विरासत का जीवंत अनुभव किया।

पीलीभीत में फर्जी कॉल सेन्टर का खुलासा, 3 गिरफ्तार

9 मोबाइल, 2 लैपटाप, 59500 रुपए नकद व अन्य सामान बरामद

पीलीभीत। पुलिस साइबर फ्रॉड से संबंधित फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने खुलासा करते हुए बताया कि एनसीआरपी पोर्टल से प्राप्त थाना स्थानीय क्षेत्र के पॉश वेरिफिकेशन तथा जनपद से संचालित साइबर अपराधों में लिप्त बैंक खातों की छानबीन के क्रम में ज्ञात हुआ कि घुंघचाई क्षेत्र में संचालित गौरव शर्मा के जनसेवा केन्द्र/बीसी प्वाइंट को होल्ड किया गया है। गौरव शर्मा से पूछताछ के क्रम में तथा सूचना मुखबिरी व सर्विलांस के माध्यम से अमृतपाल सिंह पुत्र गुरप्रीत निवासी हरीपुर अजीतपुर बिल्हा थाना घुंघचाई जनपद पीलीभीत को 6 मोबाइल फोन, 2 लैपटाप, 5 फर्जी आधार कार्ड छायाप्रतियां व 1 आधार कार्ड, 7 बैंक पासबुक, 3 चैकबुक, 1 एटीएम, 9 सिमकार्ड (खुरचे हुए), 1 वअए का पहचान पत्र, 1 दुबई का सिम, अन्य व्यक्ति का 1 पैन कार्ड व ड्राइविंग लाईसेंस, एक मोबाइल चार्जर तथा 59500 रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ से इसके 2 अन्य साथी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र छंगेलाल निवासी ग्राम उदरहा थाना घुंघचाई जनपद पीलीभीत, प्रियांशु दीक्षित पुत्र

मैकूलाल दीक्षित निवासी ग्राम व थाना घुंघचाई को भी गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ पर गिरोह सरगना अमृतपाल ने बताया कि वह अपने एक अन्य साथी के साथ वर्ष 2024 में दुबई गया तथा वहां पर कॉल सेन्टर में नौकरी की, जहां पर उसे 35000 रुपए प्रतिमाह दिये जाते थे। जब वहां पर उसने तथा उसके कथित साथी ने काम सीख लिया तो वह वापस दुबई से अपने घर आ गये तथा अपने घर से कॉल सेन्टर संचालित करने लगे। गेमिंग एप (एवियेटर, रम्मी) के जरिये लोगों को फोन करके गेम खेलने के लिए प्रेरित करते तथा पहले ईनाम जीतने पर ऊंची रकम का झांसा देते थे। सर्वप्रथम व्यक्ति जब पहली बार गेम खेलता तो उसे ऊंची दरों से जितवा देते थे तथा उनके अकांउट में पैसा भी भेज देते थे। इस प्रकार पीड़ित व्यक्तियों के खातों की डिटेल गिरोह के पास आ जाती थी।

बाद में यह लोग पीड़ित व्यक्ति का पूरा अकाउंट खाली कर देते थे। डार्क बेव से यह लोग गेम खेलने वाले इच्छुक व्यक्तियों का विवरण फोन नम्बर इत्यादि निकाल लेते है। फिर उसे अपने फोन नम्बर से फोन करके लालच देकर गेम खेलने का आदी बना देते है। जब व्यक्ति के खाते से पूरे पैसे निकल जाते है तो यह लोग अपना नम्बर बन्द कर देते है। इस सम्बन्ध में अमृतपाल के मोबाइल नम्बरों, खातों तथा लैपटाप व मोबाइल फोन में मौजूद विवरणों के सम्बन्ध में विस्तृत छानबीन की जा रही है तथा यह भी पता लगाया जा रहा है कि थाना क्षेत्र तथा जनपद में अन्य किन लोगों से अमृतपाल ने खाते लिये थे तथा सिम कार्ड खरीदे थे। गिरोह के सरगना के दूसरे साथी के सम्बन्ध में जानकारी व तलाश की जा रही है। खटक्र पोर्टल पर चैक करने पर इनके द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे खातों पर उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश प्रान्तों से साइबर फ्राड के मामलों में होल्ड लगा हुआ है, इनके द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे अन्य खातों, मोबाइल नम्बरों, आधार कार्ड, फोन के आईएमईआई तथा बैंक खातों की छानबीन कर यह पता किया जा रहा है कि इन लोगों ने सम्पूर्ण भारत वर्ष में किन-किन राज्यों से लोगों के साथ फ्राड किया है तथा इनकी शिकायतें एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज है।

नमो घाट पर तीसरे दिन बच्चों के लिए क्विज, ओरिएंटेशन और सरदार पटेल पर आधारित कटपुतली शो का आयोजन

(एजेंसी)।

काशी तमिल संगमम्‌ 4.0 के तहत नमो घाट पर तीसरे दिन नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) द्वारा बच्चों के लिए ज्ञान, रचनात्मकता और मनोरंजन से परिपूर्ण विशेष गतिविधियों का आयोजन किया गया। वाराणसी के विभिन्न स्कूलों के 600 से अधिक छात्रों की सक्रिय सहभागिता ने इस दिन को अत्यंत उत्साहपूर्ण और ज्ञानवर्धक बनाया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सरदार वल्लभभाई पटेल की जीवनी पर आधारित प्रेरक कटपुतली शो रहा, जिसे उनकी 150वीं जयंती की स्मृति में प्रस्तुत किया गया। क्रिएटिव पपेट थिएटर ट्रस्ट, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत इस शो का नेतृत्व ठइळ के श्री मणि भूषण ने किया। बाल विद्यालय (143 छात्र), देहरादून स्कूल वाराणसी (46 छात्र) तथा त्रिदंडी देव वेद पाठशाला (30 छात्र) सहित अनेक स्कूलों के बच्चों ने इस प्रस्तुति के माध्यम से लौहपुरुष

के संघर्ष, समर्पण और राष्ट्रीय एकता में उनके योगदान को समझा।

इसी क्रम में टीम एनसीसीएल द्वारा 'वाराणसी झ एक विरासत नगरी' विषय पर रोमांचक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसने बच्चों को शहर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रों ने बड़ी उत्सुकता के साथ विभिन्न राउंड्स में हिस्सा लिया और काशी की समृद्ध विरासत के बारे में नया ज्ञान अर्जित किया। इसके अलावा, 'रीडिंग एंड पब्लिशिंग' पर एक विशेष ओरिएंटेशन सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को पठन संस्कृति, पुस्तकों की दुनिया और प्रकाशन की प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना और साहित्यिक सृजन की ओर प्रेरित करना था।

इन सभी गतिविधियों में बच्चों के उत्साहपूर्ण सहभाग और शिक्षकों के सहयोग ने काशी तमिल संगमम्‌ 4.0 के तीसरे दिन को ज्ञान, सांस्कृतिक समझ और रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना दिया। वाराणसी के विद्यार्थियों ने न केवल मनोरंजन प्राप्त किया, बल्कि अपनी परंपरा, इतिहास और राष्ट्र-निमार्ताओं के योगदान की गहन समझ भी विकसित की।

नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड अब डिजिलॉकर पर उपलब्ध

(एजेंसी)।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाय) के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) ने विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से, डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड (पीवीआर) की सुविधा उपलब्ध कराकर नागरिक सेवाओं में एक बड़े विस्तार का ऐलान किया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिलॉकर, एक सुरक्षित, क्लाउड-आधारित प्लेटफार्म है, जो डिजिटल दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने, संग्रहित करने, साझा करने और सत्यापित करने में मददगार है।

नागरिकों के लिए दस्तावेज प्रबंधन को सरल बनाकर और भौतिक रिकार्ड्स पर निर्भरता को कम करते हुए यह पहल, डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस एकीकरण के साथ, पासपोर्ट सत्यापन रिकार्ड को अब डिजिलॉकर व्यवस्था में सुरक्षित रूप से एक्सेस, संग्रहित, साझा और डिजिटल रूप से सत्यापित किया जा सकता है, जिससे कागज रहित, संपर्क रहित और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ावा मिलेगा।

सफल सत्यापन के बाद, नागरिक अपने डिजिलॉकर खाते के "जारी किए गए दस्तावेज" भाग में अपने पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड देख सकते

हैं। यह पहल नागरिकों के लिए आधिकारिक सत्यापन दस्तावेजों (ओवीडी) की सुविधा और पहुँच को बढ़ाएगा, और यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके रिकॉर्ड डिजिलॉकर में सुरक्षित, विश्वसनीय और डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य रहें।

डिजिलॉकर पर पीवीआर की उपलब्धता नागरिकों को कई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करती है:

सुविधा और किसी भी समय पहुँच: सफल सत्यापन के बाद नागरिक, भौतिक प्रतियाँ साथ रखने या संग्रहित किए बगैर, वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन, दोनों के जरिए अपने डिजिलॉकर खाते के "जारी किए गए दस्तावेज" भाग से अपने पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड को आसानी से हासिल कर सकेंगे।

तेज प्रक्रियाएँ और कम कागजी कार्रवाई: पीवीआर तक डिजिटल पहुँच से यात्रा, रोजगार और अनुपालन जैसे मामलों में सत्यापन संबंधी प्रक्रियाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है, जिससे मैनुअल कागजी कार्रवाई कम होगी और सत्यापित पासपोर्ट रिकॉर्ड पर निर्भर रहने वाले नागरिकों और संस्थानों, दोनों के लिए समय की बचत होगी।

सुरक्षित, छेड़छाड़-रहित और प्रामाणिक रिकॉर्ड: डिजिलॉकर के जरिए उपलब्ध कराए गए पीवीआर, संबंधित सरकारी प्रणालियों द्वारा सीधे डिजिटल रूप में जारी किए जाते हैं, जो डिजिलॉकर की सुरक्षित संरचना के मुताबिक प्रमाणिकता, अखंडता और किसी भी तरह की छेड़छाड़ से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

आसान डिजिटल साझाकरण और सत्यापन: नागरिक, डिजिलॉकर के जरिए अधिकृत अनुरोधकर्ताओं के साथ अपने पीवीआर को डिजिटल रूप से साझा कर सकेंगे, जिससे तत्काल, सहमति-आधारित पहुँच और सत्यापन मुमकिन होगा, और सत्यापित फोटोकॉपी या कई भौतिक कॉपी देने की जरुरत कम होगी।

कागज रहित और हरित शासन के लिए समर्थन: पासपोर्ट-संबंधी सत्यापन रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटल वर्कफ़्लो में बदलकर, यह पहल कागज रहित शासन, संसाधन दक्षता और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार प्रशासनिक प्रथाओं की दिशा में सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाती है।

पीवीआर का डिजिलॉकर के साथ एकीकरण नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण और भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड को उपयोगकर्ता-अनुकूल पहुँच के साथ जोड़कर 'नागरिक-प्रथम' के दृष्टिकोण को मजबूत करता है, जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने टीबी मुक्त भारत की दिशा में प्रगति की रफ्तार तेज करने के लिए बिहार के सांसदों के साथ बातचीत की

मजबूत राजनीतिक नेतृत्व, सामुदायिक जन आंदोलन और रोगी-केंद्रित देखभाल का आ'ान किया

बिहार के सांसद टीबी मुक्त भारत के लिए एकजुट हुए, भारत के टीबी उन्मूलन मिशन के प्रति समर्थन और प्रतिबद्धता दोहराई

टीबी मुक्त बिहार के लिए एकजुट संकल्प: श्री नड्डा ने जन आंदोलन और रोगी-केंद्रित देखभाल का आ'ान किया

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सांसदों के साथ इसी तरह की बातचीत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार के सांसदों के साथ भी चर्चा की

(एजेंसी)।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली स्थित विस्तारित संसद भवन एनेक्सी में बिहार के सांसदों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जो 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के तहत गहन संपर्क अभियान का हिस्सा है। पिछले दो दिनों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सांसदों के साथ इसी तरह की बैठकों के बाद यह सत्र आयोजित किया गया और आने वाले हफ्तों में टीबी के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए राज्य-स्तरीय परामर्श की योजना भी बनाई गई है।

आज की बैठक में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन

सिंह, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री राम नाथ ठाकुर, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी, केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे के अलावा बिहार राज्य के सांसद भी उपस्थित थे।

सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को एक साथ लाकर, "टीबी मुक्त भारत के लिए सांसदों की भागीदारी" नामक इस कार्यक्रम ने भारत में टीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से प्रगति करने के लिए एकीकृत राजनीतिक संकल्प को और मजबूत किया है।

समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने टीबी उन्मूलन की दिशा में तेजी से हो रही प्रगति पर प्रकाश डाला और बताया कि देश में 2015 और 2024 के बीच टीबी के मामलों में 21% की गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी है, साथ ही 90% उपचार सफलता दर भी है, जो विश्वव्यापी औसत से अधिक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्क्रीनिंग, सामुदायिक स्तर पर पहुँच और रोगी सहायता की दिशा में हो रही बिहार की महत्वपूर्ण प्रगति, भारत की राष्ट्रीय तरक्की को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों से टीबी उन्मूलन के लिए जन आंदोलन को आगे बढ़ाने में नेतृत्व संभालने का आग्रह किया:

अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक कमियों को कम करने के प्रयास करना

निक्षय शिविरों और समुदाय-आधारित जाँच के जरिए शीघ्र पहचान को बढ़ावा देना, जिसमें लक्षणहीन संवेदनशील समूह भी शामिल हैं

ज़िला और ब्लॉक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण टीबी सेवाओं की निगरानी को मजबूत करना

सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और टीबी रोगियों को पोषण, मनोवैज्ञानिक और रोजगार से जुड़ी मदद देने के लिए निक्षय मित्रों को संगठित करना

श्री नड्डा ने जोर देते हुए कहा कि टीबी मुक्त भारत केवल एक स्वास्थ्य पहल नहीं है, बल्कि सामूहिक इच्छाशक्ति और सक्रिय राजनीतिक नेतृत्व द्वारा संचालित एक जन-नेतृत्व वाला आंदोलन है।

सत्र के दौरान, बिहार के सांसदों ने जागरूकता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण निदान और रोगी-केंद्रित देखभाल को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही समुदायों को टीबी उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने भारत की उभरती रणनीति की रूपरेखा पेश की, जिसमें एआई-सक्षम निदान का विस्तार, गहन जाँच और बेहतर परिणामों के लिए रोगी सहायता में वृद्धि शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक श्रीमती आराधना पटनायक ने 'टीबी मुक्त भारत अभियान' के तहत हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया और उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला, जहाँ संसदीय नेतृत्व बिहार की प्रतिक्रिया को और मजबूत कर सकता है।

ँ३३स्र२://२३३.स्र्.ङ्क५.ल्ल/ह१३ीफ ीङ्के/४रीथ्र ीर्/ी004व8टद्द.स्र्

यह चर्चा टीबी-मुक्त बिहार और टीबी-मुक्त भारत की दिशा में राजनीतिक सहमति और जमीनी स्तर पर रफ्तार तेज करने के मंत्रालय के